

## प्राक्कथन

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों और लेखा एवं लेखापरीक्षा पर विनियमावली, 2007 के अनुसार तैयार किया गया है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम(एनएचडीपी) का अनुमोदन किया (जनवरी 2005) है जिसमें ₹ 2,47,635 करोड़ की अनुमानित लागत पर सड़कों के 55,225 कि.मी. (31 मार्च 2013 तक) के विकास की परिकल्पना की गई थी। ऐसी सड़कों के विकास को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपा गया था जिसको सात चरणों में कार्यान्वित करना था। एनएचडीपी के चरण I और II में परियोजनाओं को मुख्यतः इजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु लिया गया था। इस मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं को पूर्ण रूप से भारत सरकार/एनएचएआई द्वारा वित्त पोषित किया गया था। चरण II के बाद से कम बजटीय संसाधनों के प्रवाह में अतिरिक्त संवर्धन और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर, भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अन्तर्गत एनएचडीपी परियोजनाए देना आरम्भ कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने पीपीपी मोड के अन्तर्गत दी गई कुल 207 परियोजनाओं में से (31-3-2012 तक) एनएचडीपी के चरण II, III, IV और V के अन्तर्गत 94 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए एनएचएआई की निष्पादन लेखापरीक्षा की थी।

लेखापरीक्षा के निष्पादन में लेखापरीक्षा एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।